















# संपादकीय

## यह कैसी कृतनीति

वा इट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और युक्ती राष्ट्रपति जेलेस्की के बीच शुक्रवार को जिस तह की तीखी नोकझोक देखने को मिली, उसे कृतनीति के इतिहास में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। लाइव टीवी कवरेज के जरिए पूरी दुनिया ने घपली बार देखा कि दो राष्ट्राध्यक्ष अपनी टीम के साथ एक-दूसरे से तू-तू मैं-मैं कर रहे हैं।

बात सही, तरोका गलत : वैसे, दोनों पक्षों के स्टेंड पर गौर करें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती जिसे सिरे से गलत कहा जाए। रूस-यूक्रेन युद्ध को तीन साल से ज्यादा हो रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध में लगातार युक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अब अगर उसे लगता है कि अपने देश के करताराओं का पैसा इस लाई इमें नहीं ज्ञोका जाना चाहिए, तो इसमें कूल भी असंत नहीं है। इस लिहाज से उसकी यह कोशिश जायज है कि यह लाई इलाई जल्द से जल्द बढ़ हो।

सुरक्षा गारंटी का सवाल : दूसरी तरफ, यूक्रेन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि युद्धविराम के बाद रूस फिर से हमला न करें। कारण यह जो भैंठे, उसकी यह शिकायत तथ्यात्मक रूप से सही है कि रूस अलग-अलग बहानों से उस पर हमले करता रहा है, सहमतियां तोड़ता रहा है। ऐसे में जहां अमेरिका पहले समझौता और

दो देशों के बीच सहमति बनने से पहले इस तरह का गतिशील आना कोई नहीं या अस्वाभाविक बात नहीं है। नवी बात यह हुई कि इन मतभेदों पर वर्त्ता मिडिया के सामने शुरू हो गयी। चूंकि बातचीत वाइट हाउस में हो रही थी, इसलिए स्वाभाविक ही इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर आ जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध भी उत्तीर्ण इसमें इस पूरी नोकझोक को ग्रेट रेलिंगिंग करार दिया।

आगे क्या : मकसद चाहे जो भी रहा हो, इस पूरे प्रकरण से दोनों में से कोई भी वृक्ष फारदे में नहीं दिख रहा।

अमेरिका जो समझौता यूक्रेन के साथ करना चाहता था, वह टल गया। यूक्रेन को भले ही यूरोप का साथ मिलता दिख रहा है, अमेरिकी समर्थन के बगैर उसका इस युद्ध में टिकना मुश्किल है। ऐसे में बहुत सभ्य है कि देश-सभर दोनों फिर बातचीत की टेबल पर आ जाएं। बेहतर होना कि इंतजार में ज्यादा वक्त और जिंदगियां न बर्बाद की जायें।

### अभिमत आजाद सिपाही

ब्लूम वैर्स की इंडस वैली की वार्षिक रिपोर्ट 2025 भारत की आर्थिक विषयता की यह तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट का सरकार द्वारा किसी तरह प्रतिवाद नहीं किये जाने से साफ़ जाहिर है कि देश की आर्थिक सेहत एकत्रणा जा रही है। अमीरी और गरीबी की खाई का घौँड़ा होना जारी है। रिपोर्ट में इस बात पर अतिरिक्त खर्च करने के असरहृष्ट हैं। लोग जरूरत के अलावा सामान या सुविधाएं नहीं खरीद सकते। वही, देश के केवल 10 फीसदी लोग, अर्थात् 13-14 करोड़ लोग देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग ही सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और देश की तरकीकी में बड़ा रोल निभाते हैं। केंद्र सरकार एक तरफ देश में तात्कालीन नया मॉडल पेश करते हुए विकसित भाव की तरफ बदल करदोंगे का आकड़ा पेश करती है, वहीं गरीबी और अमीरी की बढ़ती खाई ने इस मॉडल पर सवालिया निशान लगा दिये हैं।

ब्लूम वैर्स की इंडस वैली की वार्षिक रिपोर्ट 2025 भारत की आर्थिक विषयता की यह तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट का सरकार द्वारा किसी तरह प्रतिवाद नहीं किये जाने से साफ़ जाहिर है कि देश की

आर्थिक सेहत एकत्रणा जा रही है। अमीरी और गरीबी की खाई का चौड़ा होना जारी है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का उपभोक्ता बाजार बढ़े रहा, 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल

आय का 57.7 प्रतिशत दिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले 1990 के 22.2 प्रतिशत से घट

# लोहरदगा/लातेहार



# लोहरदगा और लातेहार में बजट को पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने नकारा

आजाद सिपाही संवाददाता



लोहरदगा। झारखण्ड विधानसभा में सोमवार को गहरा गहरी के बीच राज्य के तेज मंत्री राजीव कण्णा किशोर ने बजट पेश किया। इसके बाद राजीवीक दलों और जैन सामाजिक की ओर से बजट पर मंथन शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के लोग बजट की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं जबकि भाजपा आजसू समेत विपक्षी खेड़े ने इसे लोक लुभावना और दिशानीं बजट बता रखे हैं।

समाजसेवी व शिक्षाविद रामचंद्र गिरी ने कहा कि झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत 2025-26 का आम बजट संतुलित है। इसमें आम जनता पर किसी भी तराफ का टैक्स लिए सरकार ने अलग से बजट में व्यवस्था किया है। इससे राज्य के आम नागरिकों पर कोई टैक्स का बोझ नहीं लगेगा।

शहर के प्रध्यायत दर्ता चिकित्सक सह समाजसेवी डॉ. किशोर टी साहू ने कहा कि, राज्य सरकार ने बजट को संतुलित करने का प्रयास किया गया है पर, युवाओं और विद्यार्थियों की अनदेखी की गई है। सार्वजनिक उड़ाकम की कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने से कंपनियों अंततः जनता सही इसका भार बसुलेगी जिससे महंगाई बढ़ेगा।

भाजपा जिलाध्यक्ष मनीर उरांव ने कहा कि झारखण्ड सरकार का बजट राज्य के विकास को नहीं बढ़ावा और जैन देगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में विशेष व्यवस्था की गयी है। सार्वजनिक उड़ाकम की कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने से कंपनियों अंततः जनता सही इसका आवश्यकता थी।

कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष हाजी शकील अहमद ने कहा कि, झारखण्ड सरकार का बजट राज्य के विकास को नहीं बढ़ावा और जैन देगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को संतुलित करने का प्रयास किया गया है पर, युवाओं और विद्यार्थियों की अनदेखी की गई है। सार्वजनिक उड़ाकम की कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने से कंपनियों अंततः जनता सही इसका भार बसुलेगी जिससे महंगाई बढ़ेगा।



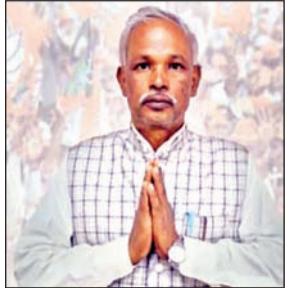
# धनबाद/बोकाटो/बेटमो

## कोयलांचल में बजट पर आयी मिली-जुली प्रतिक्रिया विधायक ने बाबुओं का बजट करार दिया

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। विधायक राज सिन्हा ने झारखण्ड विधानसभा में आज पेश वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट का मूल आकार एक करोड़ 45 लाख 400 रुपये का है। उत्तम करने की दिशा में बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अत्यंत निराशजनक बजट के अवसर उत्पन्न करने के लिए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बजट को ध्यान से देखने पता चलता है कि यह अबुआ बजट नहीं बल्कि बबुआ या बाबुओं का बजट है। पिछले बजट से वित्तीय वर्ष 25-26 का आकालन के पास किया गया है कि मद और किस अवधि का है तो राज सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। बजट में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि राज सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। अतः यह बजट पूरी तरह से भ्रामक है और फेंड के बदौलत झारखण्ड के मजदूर, किसान, दलित, पीढ़ी, शाषित, वर्चित और अपनी पीठ व्यथापाने का कार्य करता है। यह बजट राज्यहित में नहीं। चुनाव के पूर्व किये गये वादों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ना तो शिक्षा ना तो कृषि क्षेत्र में ना ही रोजगार सूची नहीं है। जनता के ऊपर कोई भी विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बजट को ध्यान से देखने पता चलता है कि यह अबुआ बजट है।

नगर विकास को बढ़ावा देते हुए रोजगार सूजन करने में न ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में न ही किसान की आय को दोगुना करने के लिए नहीं पर्यटक क्षेत्र बनाकर। अत्यंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट का मूल आकार एक करोड़ 45 लाख 400 रुपये का है। आकार 128900 करोड़ रुपये का था। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बजट को ध्यान से देखने पता चलता है कि यह अबुआ बजट नहीं बल्कि बबुआ या बाबुओं का बजट है। केंद्र सरकार की योजनाओं और फेंड के बदौलत झारखण्ड की जो बढ़ोतारी हो रही है उस पर झारखण्ड की हेमंत सरकार अपनी पीठ व्यथापाने का कार्य करता है। लौगंग, कल, करारायाओं के क्षेत्र में भी कुछ भी विशेष प्रबंध इस बजट में नहीं है। कुल मिलाकर वह बजट सिर्फ आंकड़ों का लोक लुभावना खेल मात्र है। जिला मंत्री प्रियंका देवी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने बजट में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गयी है।



बजट में कुछ भी नहीं। जिला महामंत्री मानस प्रसाद और धर्मेश्वर महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम बजट निराशजनक और जन विरोधी बजट में सरकार ने बड़-बड़ वाद तो किये हैं, लौगंग जिली निकोकत को देखते हुए यह बजट पूरी तरह से खोखोता है। जिला मंत्री प्रियंका देवी ने कहा कि बजट को ध्यान से देखने पता चलता है कि यह अबुआ बजट है।

### झारखण्ड को विकास की ओर ले जाने वाला बजट: ब्रजेंद्र सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। झारखण्ड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा पेश किया गया है। जिसमें सोशल सेक्टर का विशेष ध्यान के साथ-साथ सरकार ने अंतिम पायदान पर खड़े राज्य के कमज़ोर गरीबों वर्चितों और महिलाओं के बारे में सबसे अधिक सोचा है और उसी पर सरकार काम करने जा रही है। सामाजिक सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा लाख किसानों के लिए वापसी



नियमों के लिए विकास की ओर ले जाने वाला बजट है।

जिसमें व्यापारी विद्युत क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। जिसमें व्यापारी विद्युत क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है।

सभी विभागों का ध्यान सरकार ने रखा है। शिक्षा के क्षेत्र को नयी उड़ान दी गयी है मेडिकल के साथ-साथ मास क्युनिकेशन विजेन्स के कोर्नेल खुलेगे जिसमें कि झारखण्ड के छात्राओं को दूसरे प्रदेशों में उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। झारखण्ड ने अपने वित्तीय घाटे को कम किया है व्यापार के क्षेत्र में नीति आयोग ने भी माना है देश में झारखण्ड चौथे नंबर में है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में झारखण्ड पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है।



जिसका फायदा इस बार चार लाख किसानों को होगा तथा

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार की ओर ले जाने वाला बजट: ब्रजेंद्र सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार अपने टेनोर का

पहला वित्तीय बजट 2025-26

पेश किया है, जिसमें सोशल

सेक्टर का विशेष ध्यान के

साथ-साथ सरकार ने अंतिम

पायदान पर खड़े राज्य के

कमज़ोर गरीबों वर्चितों और

महिलाओं के बारे में सबसे

अधिक सोचा है और उसी पर

सरकार काम करने जा रही है।

सामाजिक सेक्टर पर विशेष

ध्यान दिया गया है, साथ ही

साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा

लाभ किसानों के लिए वापसी

करते हुए कहा कि नेशनल

पुलिस कमिशन के मानक के

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार की ओर ले जाने वाला बजट: ब्रजेंद्र सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार अपने टेनोर का

पहला वित्तीय बजट 2025-26

पेश किया है, जिसमें सोशल

सेक्टर का विशेष ध्यान के

साथ-साथ सरकार ने अंतिम

पायदान पर खड़े राज्य के

कमज़ोर गरीबों वर्चितों और

महिलाओं के बारे में सबसे

अधिक सोचा है और उसी पर

सरकार काम करने जा रही है।

सामाजिक सेक्टर पर विशेष

ध्यान दिया गया है, साथ ही

साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा

लाभ किसानों के लिए वापसी

करते हुए कहा कि नेशनल

पुलिस कमिशन के मानक के

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार की ओर ले जाने वाला बजट: ब्रजेंद्र सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार अपने टेनोर का

पहला वित्तीय बजट 2025-26

पेश किया है, जिसमें सोशल

सेक्टर का विशेष ध्यान के

साथ-साथ सरकार ने अंतिम

पायदान पर खड़े राज्य के

कमज़ोर गरीबों वर्चितों और

महिलाओं के बारे में सबसे

अधिक सोचा है और उसी पर

सरकार काम करने जा रही है।

सामाजिक सेक्टर पर विशेष

ध्यान दिया गया है, साथ ही

साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा

लाभ किसानों के लिए वापसी

करते हुए कहा कि नेशनल

पुलिस कमिशन के मानक के

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार की ओर ले जाने वाला बजट: ब्रजेंद्र सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। हेमंत है तो हिम्मत है

अबुआ सरकार अपने टेनोर का

पहला वित्तीय बजट 2025-26

पेश किया है, जिसमें सोशल

सेक्टर का विशेष ध्यान के

साथ-साथ सरकार ने अंतिम

प

